एन वाई एस ई में प्रधानमंत्री का भाषण

22 सितम्बर, 2004

न्यूयार्क

" मैं प्रतिष्ठित व्यवसायियों के समूह विश्व के पूँजीगत समुदाय के प्रवर सदस्यों के बीच अपने को पाकर धन्य महसूस कर रहा हूँ । प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि दूसरे देशों में जाकर व्यापार करने वालों को अपने समाज में काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि वित्त के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों सहित सभी प्रकार के व्यापारियों को सभ्यता की संभावनाओं का परम संरक्षक माना जाता था । इसीलिए, मैं आपका एवं उन संस्थाओं का, जिनके आप प्रतिनिधि हैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने आर्थिक संपन्नता लाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका अदा की है तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों तक विकास के इस लाभ को पहुँचाया है । इससे आर्थिक संपन्नता लाने की प्रकियाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की कर्त्तव्यनिष्ठा बढ़ी है ।

भारत ने अपने लंबे तथा उतार- चढ़ाव भरे इतिहास में वर्ष 1991 में एक नए अध्याय का श्रीगणेश किया । हमारी अर्थव्यवस्था सदा से कमोबेश मुक्त अर्थव्यवस्था रही है । लेकिन हमारे यहां बड़ी संख्या में उपलब्ध नौकरशाही और कुछ हद तक नियामक तंत्र ने विरासत में प्राप्त जोखिम एवं उद्यमी भावना को जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है फलने फूलने में बाधाएं उत्पन्न की हैं ।

वर्ष 1991 में, हमने अपने आर्थिक जीवन में उस प्रकिया को बदलने, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए । हमने यह निर्णय किया कि विश्व की परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के साथ स्वयं को जोड़ने में ही भारत का भविष्य निहित है तभी भारत की छुपी हुई विकास की अपार क्षमताओं को पूरी तरह साकार किया जा सकता है । हमने यह भी निर्णय किया कि प्रत्यक्ष एवं संस्थागत दोनों ही प्रकार के विदेशी निवेश को अंतरित करने हेतु और अधिक शक्तिशाली दृष्टिकोण अपनाना होगा ।

अमरीका के व्यापार समुदाय एवं इस देश में पूंजी निवेश से जुड़ी हुई महिलाओं एवं पुरुषों के योगदान से तथा उनसे मिले सहयोग से मैं बहुत खुश हूँ । लेकिन आज मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि हमने इसके परिणामों का प्रदर्शन मात्र किया है । जैसा कि मैंने राष्ट्रपति बुश से अनुरोध किया है कि अमरीका के साथ भारत के रिश्ते सही दिशा में बढ़ रहे हैं । किंतु अभी प्रतिभा के विकास की अपार संभावनाएं शेष हैं जिनका दोहन किया जाना बाकी है । इस अपार प्रतिभा विकास की संभावनाओं को मूर्तरूप देने की दिशा में कार्य करना हमारा कर्त्तव्य है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह यकीनन संभव है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो अभी आना है । और मैं यहाँ आपको यह संदेश देने के लिए आया हूँ कि गरीबी, अज्ञानता एवं बीमारी के विरूद्ध जिनसे अभी भी हमारे देश में करोड़ो लोग प्रभावित हो रहे हैं, भारत की लड़ाई में आपकी सक्रिय भागीदारी करें और रूचि लें । तभी हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे ।

यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और हम इस संकल्प के लिए वचनबद्ध हैं । लेकिन विकास के इस अनूठे प्रयोग और लोकतांत्रिक सहअस्तित्व से सफलता प्राप्त

करने के लिए हमें विश्व के व्यापारिक एवं पूँजीगत समुदाय का सक्रिय सहयोग और भागीदारी चाहिए । भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जहां की आबादी लगभग एक अरब दो करोड़ (1.2 बिलियन) है । हमारे देश में विश्व के सभी महान धर्मों का समावेश है । हमारे देश में 150 मिलियन से अधिक मुस्लिम आबादी है जो संभवतः मुस्लिम देश कहलाने वाले किसी अन्य देश की मुस्लिम आबादी से अधिक है, हमारा समाज यथार्थ रूप में बहु-धर्मी, बहु- सांस्कृतिक एवं बहु -भाषी है । ऐसी विविधताओं में भी एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है । भारत की दयनीय आर्थिक संरचना में लोकतांत्रिक मूल्यों में अपने विश्वास को न्यायिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को, मौलिक मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए ऐसा करना कोई सहज कार्य नहीं है । फिर भी हम अपने संकल्प पर दृढ़ रहे हैं ।

इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए हमें अमरीका सहित अन्य मित्र राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त होता रहा है । आज, भारत, विश्व में तीव्रगति से विकास कर रहे देशों की कतार में खड़ा है । जब से हमने आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं तब से हमारी अर्थव्यवस्था औसतन 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है । हमारी ऐसी महत्वाकांक्षा है और हम यह आशा भी करते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर बढ़कर 7 से 8 प्रतिशत या इससे भी अधिक होगी । हम अपने महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के कठोर निर्णय लेंगे । यह संभव है, और वास्तव में जब 90 के दशक में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, हमने आर्थिक वृद्धि 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक, औद्योगिक वृद्धि 12-13 प्रतिशत से अधिक, निर्यात वृद्धि दर 20 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, और मैं चाहता हूं कि जो वृद्धि

दर हमने 90 के मध्य में दर्ज की थी उसे पुनः प्राप्त किया जाए । इस सबके लिए हमें आपके सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी की जरूरत है । भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत करता है । भारत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय, संस्थागत निवेशकों का स्वागत करता है । हम व्यावसायिक समुदायों तथा अमरीका के वित्तीय समुदायों के साथ नई साझेदारी की तलाश कर रहे हैं , और मैं यहाँ आपको उपदेश देने नहीं वरन आपसे यह जानने के लिए आया हूँ कि किस प्रकार से दोनो देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में छुपी हुई अपार संभावनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है । भारत की सरकार के रूप में आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं ? आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की राह में साहस एवं उद्यम, जोखिम उठाने आदि की भावना को बढ़ाने हेतु किस प्रकार हम और अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं ?

भारतीय समाज उदार है और हम आज ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्रांति यहाँ तक कि दुनियां के दूरस्थ स्थानों पर क्या हो रहा है, इससे संबंधित सूचना प्रत्येक घर की दहलीज तक पहुँच रही है । इस प्रकार भारत एक खुली किताब है । हम इस बात से चिंतित होते रहे हैं कि हमारे समक्ष अनेक चुनौतीपूर्ण कार्य पड़े हैं । आजकल मैं गठबंधन की सरकार चला रहा हूँ, यह एक ऐसी मिली-जुली सरकार है जिसमें अनेक वामपंथीदल शमिल हैं । ये दल हमें बाहर से समर्थन दे रहे हैं । आपमें से अनेक लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि इतनी विविधता के साथ जब आप मिलीजुली सरकार चला रहे हो तो इन बदली हुई परिस्थितियों में 1991 में प्रारंभ की गई प्रक्रिया को कैसे पूरा कर पाओगे ? मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यह कार्य किया जा सकता है और हम इसे संपन्न करेंगे । मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज नए परिवर्तन की हवा बह रही है । मैं अक्सर कहता हूँ कि

राजनेताओं की कसौटी यह नहीं होनी चाहिए किं वे विपक्ष में बैठकर क्या-क्या मुददे उठाते हैं ? बल्कि यह होनी चाहिए कि वे सत्ता मे आकर क्या कर पाते हैं ? हमारे देश के एक प्रमुख राज्य में कम्युनिस्टों द्वारा शासित सरकार है । और यदि आप, विदेशी निवेश का स्वागत करने, बाहर से अधिकाधिक उद्यमियों के प्रवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में उस सरकार के पिछले रिकार्ड को देखें तो आप पाएंगे कि समूचे देश में यह परिवर्तन की हवा का एक संकेत है ।

मैं आम सहमति बनाने में आने वाली कठिनाइयों को कम नहीं आंकता लेकिन मैं इस बात में भी विश्वास करता हूँ कि एक ऐसी आम सहमति जो उन्मुक्त चर्चा, सक्रिय विचार-विमर्श पर आधारित हो तो वह सुधार प्रक्रिया को पहले की तुलना में आगे बढ़ाने में अधिक स्थायी होगी । यदि आज हम 70 से 80 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम एक व्यापक सार्थक एजेंडा तैयार कर सकते हैं, शायद भारत के इतिहास में जितना लोकप्रिय " सभी के लिए भोजन" कार्यक्रम हुआ है उतना पहले कोई कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं हुआ । हमने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया है । इसमें कई बातें शामिल हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं - हम यह मानते हैं कि भारत को सर्वप्रथम संस्थागत और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के अतिरिक्त विदेशी निवेश की जरूरत है , हमारी सरकार ने ऐसे पूँजीगत बाजारों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है, जो पारदर्शिता को बढ़ावा दें और संस्थाओं एवं मजबूत तथा पक्षपातरहित नियामक शासन का सम्मान करें ।

अतः मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सुधार प्रकिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास सभी साधन हैं । इसके विपरीत कुछ आवाजें उठती रही हैं , लेकिन ये किसी

भी कार्यशील लोकतंत्र में किसी निर्णय पर पहुँचने की प्रक्रियाओं के अभिन्न अंग है और भारत को अपने कार्यशील लोकतंत्र पर गर्व है । इसमें न तो कोई संदेह है और न ही कोई समस्या । जब मैं व्यापारी वर्ग से बात करता हूँ तो वे कहते हैं कि भारत में बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याएं हैं । हाँ, मैं सहमत हूँ कि हमारे देश में बुनियादी ढांचा ही सबसे बड़ी समस्या है किंतु यही सबसे बेहतर अवसर भी है । आने वाले 10 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हमें कम से कम 150 विलियन डालर के निवेश की आवश्यकता होगी और हमें ऊर्जा के क्षेत्र में, तेल उत्पादन, सड़क निर्माण कार्यक्रम, अपनी रेल व्यवस्था, भोजन एवं विमानपत्तनों (एयरपोर्ट) के आधुनिकीकरण के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी । ये ही वे क्षेत्र हैं जहाँ मैं महसूस करता हूँ कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी करके नए प्रयोग किए जा सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका तो हो सकती है लेकिन वह स्वयं सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है । मैं महसूस कर रहा हूँ कि भारत के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण संबंधी चुनौतियों को स्वीकार करने में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की व्यापक और बहुत ही लाभदायक भूमिका है ।

हमें अपनी नौकरशाही प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और किसी समूह विशेष की प्रक्रियाओं का प्रबंध करने की दिशा में अधिक ध्यान देना होगा । मैंने अक्सर देखा है कि विदेशों से आने वाले व्यवसायियों के समक्ष नौकरशाही प्रक्रियाएं एक बाधा बन जाती हैं । मैं मानता हूँ , लेकिन नौकरशाही एक घोड़े के समान होती है, आप इसे मनचाही दिशा में ले जा सकते हैं लेकिन यह सब घुड़सवार की योग्यता पर निर्भर करता है । हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नौकरशाही प्रकियाएं, हमारी प्रगति में बाधा बनने, जोखिम और उद्यम भावना को प्रोत्साहित करने में बाधा बनने की बजाय सक्रिय रूप से

प्रोत्साहन भूमिका निभाए । हम इस क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप को कम करने का प्रयास कर रहे हैं । इसे नियमों की अधिकता के बजाय प्रोत्साहन भूमिका में बदलने का प्रयास कर रहे हैं । मैं समय-समय पर भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें सुनता रहता हूँ । फिलहाल भ्रष्टाचार के संबंध में मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि यदि हम गैर-विवेकाधिकार नियंत्रणों को अपनाएं, यदि हम अपने नियामक तंत्र को सरल बना लें, यदि हम अपनी टैक्स दरों को सरल बना लें और पक्षपातपूर्ण रवैये को हटाने की व्यवस्था कर लें, तो हम एक ऐसा वातावरण तैयार करने में सफल हो सकेंगे जिसमें गतिशीलता अधिक होगी और ईमानदार व्यवसायियों की परेशानी कम होगी ।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये सभी प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ जिससे भारत के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण एवं विस्तार हो सके और आने वाले 5 से 7 वर्षों में हम अपने बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बना सकें । मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प हूँ कि हमारी सरकारी प्रकियाएं यथासंभव पारदर्शी हों, यथासंभव व्यवसायी वर्ग एवं उद्यमियों के अनुकूल हों, और ये आर्थिक संपन्नता लाने के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निर्वाह करने वालों के प्रति सम्मानभाव प्रदर्शित करने वाली हों । मैं यह सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास करूंगा कि भ्रष्टाचार जो हमारी अनेक क्रियाकलापों में एक समस्या बन चुका है उसे रोकने, नियंत्रित करने और इसे आने वाले समय में जड़ से उखाड़ फेंकने में आवश्यक कदम उठाए जाएं । भारत 7 से 8 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज करना चाहता है लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक समुदाय के भारी सहयोग की आवश्यकता होगी । हमारी बजट एवं निवेश दर ऐसी है कि हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 26 प्रतिशत प्रतिवर्ष निवेश करने में समर्थ हैं ।

मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत की घरेलू बचत में तेजी से वृद्धि होगी क्योंकि कई अन्य देशों से भिन्न हमारे देश में कुल आबादी में से रोजगार-योग्य आयु वर्ग की आबादी का अनुपात बहुत तेज गति से बढ़ने जा रहा है और हमारे आबादी विशेषज्ञ इस संदर्भ में हमें बताते हौ कि इससे बचत करने की क्षमता में भारी वृद्धि होनी चाहिए । यदि हम बचत क्षमता को बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो हमें वित्तीय दस्तावेजों एवं वित्तीय संस्थाओं को सही दिशा देनी होगी जिससे बचतकर्ता एवं निवेशक और अधिक प्रभावी ढंग से आकर्षित हों और यही वह क्षेत्र है जिनमें मैं अपने देश में वित्तीय सेवा उद्योग की बढ़ती संभावनाओं को देख रहा हूँ । हमने अपने वित्तीय सेवा उद्योग को बाहरी निवेशकों की भागीदारी के लिए खोल दिया है । लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ और स्वीकार भी करता हूँ कि इन क्षेत्रों में अभी और अधिक गति लाने की आवयकता है । मैं यहाँ आज इन क्षेत्रों में आपके सहयोग, मार्गदर्शन एवं आपके विचार जानना चाहता हूं कि हम एक साथ कार्य करके कैसे यह सुनिश्चित करें कि आने वाले वर्षों में भारत बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक शक्ति बनकर उभरे । हमारी यह महत्वाकांक्षा है कि जो कुछ भी हम कर चुके हैं उससे बेहतर प्रदर्शन किया जाए । लोग कहते हैं कि अगली शताब्दी एशिया की होगी । मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ और न ही मैं पूर्वानुमान करने की क्षमता रखता हूँ । फिर भी जो व्यक्ति पूर्वानुमान करते हैं उनके बारे में मुझे बताया गया है कि जब इन व्यक्तियों का पूर्वानुमान सही साबित हो जाता है तो यदि हम दांते के शब्दों में कहें तो उनकी भर्तस्ना की जाती है । किंतु मेरा एक सपना है जिसे मैंने 1991 के बजट प्रस्तुतीकरण के समय अपने कथन के रूप में प्रस्तुत किया था । मैंने सदन में " विक्टर ह्यूगो " को उद्धृत किया था, " जिस विचार के प्रयोग का समय आ गया हो उसे दुनिया की कोई ताकत साकार होने से नहीं रोक सकती है" और तब मैंने सदन में कहा था कि

"विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत शक्ति बनकर उभरेगा - इस विचार का समय आ चुका है।"

1991 के उन निराशाभरे दिनों से लेकर आज तक जब हमारी अर्थव्यवस्था 6 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, जब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार 120 विलियन डालर तक पहुँच गया है, जब भारत का निर्यात 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जब भारत का औद्योगिक उत्पादन 78 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, हमने अनेक पड़ाव तय कर लिए हैं फिर भी अभी श्रेष्ठतम का प्रदर्शन होना है । और उस सपने को साकार करने के लिए, "कृपया जोख़िम एवं उद्यम के इस नए युग में प्रवेश कीजिए और भागीदार बनिए, जिसका सूत्रपात हम भारत में करना चाहते हैं "। भारत को अमरीका के सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी की जरूरत है । हम कृतज्ञतापूर्वक राष्ट्रपति रूसवेल्ट की उस मदद को याद करते हैं जिसमें उन्होंने हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले ब्रिटिश सरकार पर यह प्रभाव डाला था कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों बाद, हमें अपनी कृषि-व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने, अपने शैक्षिक संस्थागत ढांचे का आधुनिकीकरण करने, यह सुनिश्चित करने कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा संसाधनों के माध्यम से विकास रथ चलता रहे , इन सबके लिए अमरीका से सक्रिय सहयोग एवं सहायता प्राप्त हुई है। लेकिन आज के परिदृश्य में हमारा जोर कुछ भिन्न पहलुओं पर है । आज हमने जो यह नई लहर चलाई है उसको आगे बढ़ाने एवं उसके प्रबंधन के लिए अमरीकी व्यावसायिक समुदाय और अमरीकी वित्तीय समुदाय की भूमिका को मज़बूत बनाना चाहते हैं । भारत को विकास के एक नए सोपान पर कदम रखना होगा । भारत को बदलती विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलना होगा ।

हमारी आंकांक्षा है जिसमें व्यापार वृद्धि एवं प्रौद्योगिकी निवेश-दोनों ही दृष्टि से पहले की तुलना में कहीं अधिक सहयोग मिले । इस कार्य को संपन्न करने में मैं आपसे सहायता, भागीदारी और सक्रिय सहयोग चाहता हूँ ।